राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
डी.बी. सिविल विविध अपील संख्या 934/2021

1. महाप्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे, मुख्यालय, जयपुर
2. मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे, मुख्यालय जयपुर
3. मंडल वित्त प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. एस.के. सिद्ध पुत्र राम गोपाल, बी-10, औद्योगिक क्षेत्र, रानी बाजार, बीकानेर
2. खेत सिंह एडवोकेट, एकमात्र मध्यस्थ, 128 सेंट्रल स्कूल स्कीम, जोधपुर

----प्रतिवादीगण

अपीलकर्ता(ओं) के लिए : श्री प्रतीक गट्टानी
प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री विनीत आर. दवे
श्री हर्षितभूरानी

माननीय डॉ. न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी
माननीय श्री न्यायमूर्ति मुन्नुरि लक्ष्मण
निर्णय

13/08/2024

(प्रति डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी, जे):

1. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (जिसे आगे से '1996 का अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 37 के तहत यह अपील रेलवे (संक्षेप में, 'अपीलकर्ता') द्वारा विद्वान न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 1, जोधपुर द्वारा सिविल विविध 'ए; केस संख्या/एनसीवी संख्या 03/2019 में पारित दिनांक 31.07.2021 के आदेश के खिलाफ पेश की गई है, जिसके तहत अपीलकर्ताओं द्वारा अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत दिनांक 10.09.2018 के पुरस्कार को चुनौती देते हुए प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया गया था।
2. अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ताओं द्वारा जोधपुर रेलवे स्टेशन पर एसी कोचों

और रिटायरिंग रूमों के लिए बेड रोल आइटमों की धुलाई, ड्राईक्लीनिंग, इस्त्री करने के लिए तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 14.01.2005 से 31.01.2008 के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी की गई थी और निविदा प्रक्रिया के समापन और प्रतिवादी संख्या 1-फर्म (संक्षेप में, 'प्रतिवादी') द्वारा प्रस्तावित बोली (दरों) को स्वीकार करने पर प्रतिवादी के पक्ष में 48,48,949.50/- रुपये प्रति वर्ष, जो कुल मिलाकर तीन वर्षों के लिए 1,45,46,848.50/- रुपये होती है, दिनांक 13.01.2005 को कार्य आदेश जारी किया गया था।

2.1. इसके बाद, अपीलकर्ताओं और प्रतिवादी के बीच 14.01.2005 को तीन साल की उपरोक्त अवधि के लिए एक समझौता किया गया था। बेशक, प्रतिवादी की अनुबंध अवधि 28.02.2008 तक बढ़ा दी गई थी।

2.2. समझौते की शर्तों के अनुसार, प्रतिवादी ने अपीलकर्ताओं के पास 3,00,000/- रुपये की सुरक्षा राशि जमा की। अपीलकर्ताओं ने अनुबंध अवधि के बीच में एकतरफा रूप से एक निश्चित राशि की कटौती की और प्रतिवादी पर जुर्माना भी लगाया। इसके बाद प्रतिवादी ने 13.04.2011 और 11.05.2011 के पत्रों के माध्यम से अपीलकर्ताओं के समक्ष अपना पूरा दावा प्रस्तुत किया और उस पर लगाए गए कटौतियों और जुर्माने के बारे में स्पष्टीकरण भी मांगा; अपीलकर्ताओं द्वारा दिनांक 23.06.2011 के पत्र के माध्यम से इसका उत्तर दिया गया, जिसके तहत प्रतिवादी के दावे को खारिज कर दिया गया।

2.3. प्रतिवादी के अनुसार, ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिवादी ने अपीलकर्ताओं को दिनांक 05.04.2012 को दावे के विवरण के साथ एक नोटिस भेजा और उसके बाद 30 दिनों की अवधि के भीतर समझौते के खंड 37 के अनुसार एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया। उक्त नोटिस में, प्रतिवादी ने पर्यावरण के अनुकूल बैग की आपूर्ति न करने, बिल किए गए कंबलों की संख्या में भिन्नता और ड्राई-क्लीन के कारण अपीलकर्ताओं द्वारा लगाए गए कुछ कटौतियों और दंडों पर विवाद किया है। इसके अलावा, प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी की सुरक्षा जमा से की गई एकतरफा कटौती के बारे में विवाद उठाया गया था, इस प्रकार, प्रतिवादी द्वारा उक्त नोटिस में 48,80,0875/- रुपये का दावा उठाया गया था।

2.4. जब अपीलकर्ताओं की ओर से आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई, तो दिनांक 05.04.2012 के उक्त नोटिस के अनुसरण में, प्रतिवादी ने 1996 के अधिनियम की धारा 11(6) के तहत इस माननीय न्यायालय के समक्ष एसबी सिविल विविध मध्यस्थता आवेदन संख्या 66/2015 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर, इस माननीय न्यायालय ने दिनांक 05.01.2016 के आदेश के तहत उक्त

आवेदन को स्वीकार करते हुए, श्री खेत सिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता को पक्षों के बीच विवाद को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया, और उसके बाद मध्यस्थता कार्यवाही शुरू हुई।

2.5. मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान, अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी के दावे के संबंध में आपत्ति उठाई, जिसमें ब्याज सहित कटौती की गई राशि की वापसी का दावा किया गया था, जो कि प्रश्नगत समझौते के अनुरूप नहीं था। अपीलकर्ताओं ने दावे में भिन्नता (शुरू में उठाया गया दावा, 20,99,812/-; दिनांक 05.04.2012 के नोटिस में उठाया गया दावा 48,80,875 रुपये का था; जबकि मध्यस्थता कार्यवाही में उठाया गया दावा 26,08,467 रुपये का था), विलंबित/समय बाधित दावा और दी गई परिस्थितियों में प्रतिवादी के कहने पर शुरू की जाने वाली कार्यवाही की गैर-रखरखाव, विशेष रूप से, उपरोक्त आपत्तियों और प्रश्नगत समझौते की शर्तों के मद्देनजर, के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाई। उक्त प्रारंभिक आपत्तियों को विद्वान एकल मध्यस्थ द्वारा दिनांक 02.04.2017 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया।

2.6. मध्यस्थता कार्यवाही के उचित समापन के बाद, विद्वान मध्यस्थ ने दिनांक 10.09.2018 को निम्नलिखित तरीके से अवार्ड पारित किया (जैसा कि दिनांक 31.07.2021 के आक्षेपित आदेश में पुनः प्रस्तुत किया गया है):

क्रमांक	मध्यस्थता में प्रतिवादी द्वारा उठाया गया दावा, के संबंध में:	प्रतिवादी द्वारा दावा की गई राशि	विद्वान मध्यस्थ द्वारा दी गई राशि
1.	बेड रोल की वसूली के रूप में सुरक्षा जमा राशि से अवैध कटौती	31,185/-	31,185/-
2	पर्यावरण अनुकूल बैग की आपूर्ति न करने पर अवैध कटौती	4,33,501/-	4,33,501/-
3	गैर-दावेदार द्वारा एकतरफा तरीके से लगाई गई अवैध कटौती/जुर्माना	3,50,900/-	22,500/-
4	बिल किए गए और ड्राईक्लीन किए गए कंबलों की संख्या में भिन्नता के रूप में कटौती की गई राशि	10,42,920/-	10,42,920/-
5	ब्याज	7,49,961/-	निल
कुल		26,10,454/-	15,30,086/-

2.7. अपीलकर्ताओं द्वारा दिनांक 10.09.2018 के उपरोक्त निर्णय को वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 1, जोधपुर के समक्ष अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत विविध आवेदन दायर करके चुनौती दी गई थी, जिसे वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा

दिनांक 31.07.2021 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, और उक्त आदेश तत्काल अपील में चुनौती का विषय है।

3. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी का दावा सीमा द्वारा वर्जित है और इसके संबंध में आपति विद्वान एकमात्र मध्यस्थ के साथ-साथ वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष भी उठाई गई थी, लेकिन उस पर उचित विचार नहीं किया गया, और इसलिए, आक्षेपित निर्णय के साथ-साथ आदेश को भी रद्द कर दिया जाना चाहिए और अपास्त किया जाना चाहिए।

3.1. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि संबंधित प्राधिकरण द्वारा 27.04.2009 को 57,478/- रुपए की जुर्माना राशि काटने के बाद अंतिम बिल का भुगतान किया गया, जिसके बाद 23.06.2011 को प्राधिकरण ने सभी दावों को खारिज कर दिया और प्रतिवादी द्वारा किए गए धन वापसी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया; तत्पश्चात 29.04.2015 को मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन दायर किया गया, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सीमा अवधि, जो कि 3 वर्ष है, उस समय तक समाप्त हो चुकी थी।

3.2. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में, सीमा अवधि की गणना प्रतिवादी द्वारा संबंधित प्राधिकारी के समक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रस्तुत आवेदन दिनांक 05.04.2012 की तिथि से की जानी चाहिए थी, क्योंकि अंतिम बिल का भुगतान किए जाने और अन्य दावों को खारिज किए जाने के बाद, प्रतिवादी अपने स्वयं के अधिकारों से बंधा हुआ था, जैसा कि यहां दावा किया गया है, और उसने 4 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए आवेदन दायर नहीं किया, और इसलिए, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी का दावा समय सीमा समाप्त है। इस तरह के प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने मेसर्स बी और टी एजी (मध्यस्थता याचिका (सी) संख्या 13/2023, 18.05.2023 को तय) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आगे दलील दी कि 1996 के अधिनियम की धारा 16 के खंड 2 और 3 के अनुसार यहां उठाई गई आपति पर 1996 के अधिनियम की धारा 16 के खंड 5 के तहत निर्णय लिया जाना चाहिए और यदि आपतियों को खारिज कर दिया जाता है, तो मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखी जा सकती है, जो अवार्ड पारित करने के साथ समाप्त होगी। इसलिए, आपति की अस्वीकृति के संबंध में चुनौती केवल 1996 के अधिनियम की धारा 16 के खंड 6 के अनुसार 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत पुरस्कार पारित करने के बाद ही उठाई जा सकती है, लेकिन विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने उन बिंदुओं में से किसी पर भी विचार करने से

इनकार कर दिया, जो अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए प्रारंभिक आपत्तियों का हिस्सा थे और एकमात्र मध्यस्थ द्वारा खारिज कर दिए गए थे।

3.4. विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय भी मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए अनुबंध पर लागू विशिष्ट शर्तों पर विचार करने में विफलता के आधार की जांच करने में विफल रहा, जो कि 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत की गई किसी भी चुनौती के संबंध में एक प्राथमिक आवश्यकता है। इस तरह के प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वकील ने हिंदुस्तान जिनक लिमिटेड बनाम फ्रेंड्स कोल कार्बनाइजेशन (2006) 4 एससीसी 445 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा किया।

4. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान वकील द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि अंतिम बिल का भुगतान 27.04.2009 को किया गया था और सुरक्षा जमा अंततः 15.02.2010 को जारी किया गया था, जिसके बाद, प्रतिवादी ने 13.04.2011 और 11.05.2011 के पत्रों के माध्यम से अपना दावा प्रस्तुत किया और अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी के दावों को खारिज करते हुए 23.06.2011 के पत्र के माध्यम से उसी का जवाब दिया।

4.1. इसके बाद, प्रतिवादी ने 05.04.2012 के पत्र के माध्यम से अपीलकर्ताओं से प्रश्नगत समझौते के खंड 37 के तहत विवाद को हल करने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया। इसके बाद, 04.05.2012 तक 30 दिनों तक इंतजार करने के बाद, प्रतिवादी ने 29.04.2015 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अधिनियम 1996 की धारा 11 (6) के तहत एक आवेदन दायर किया, जो स्पष्ट रूप से सीमा अवधि (यानी 3 साल के भीतर) के भीतर है, जिसकी गणना 04.05.2012 से की गई है, और इसलिए, अपीलकर्ताओं का यह तर्क कि उक्त आवेदन सीमा द्वारा वर्जित था, कोई आधार नहीं रखता है।

4.2. विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि उपरोक्त समय-सीमा के अनुसार, प्रतिवादी के दावों को 1996 के अधिनियम की धारा 21 के तहत मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने पर जीवित दावों के रूप में माना जाना चाहिए, अर्थात् नोटिस की तारीख (05.04.2012) मध्यस्थता खंड को लागू करना।

4.3. विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि दावे की स्थिरता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति समय-बाधित होने के कारण, एकमात्र मध्यस्थ द्वारा अपने

मध्यस्थता आदेश दिनांक 02.04.2017 के माध्यम से सही ढंग से खारिज कर दी गई है।

4.4. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत सभी सामग्री पर विचार करने के पश्चात् अधिनियम 1996 की धारा 34 के अंतर्गत आवेदन को खारिज कर दिया, क्योंकि अपीलकर्ता यह स्थापित करने में असफल रहे कि प्रतिवादी द्वारा उठाया गया दावा किस प्रकार भिन्नता से ग्रस्त है तथा मध्यस्थता के दायरे से बाहर है।

4.5. विद्वान वकील ने आगे कहा कि जी.सी.सी. के खंड 64 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति की 180 दिन की समय-सीमा और प्रक्रिया को प्रश्नगत समझौते के मध्यस्थता खंड 37 और खंड 2 द्वारा बाहर रखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि खंड 64 के आधार पर ऐसी कोई दलील अपीलकर्ताओं द्वारा एकल मध्यस्थ के समक्ष या अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष नहीं ली गई।

4.6. विद्वान वकील ने यह भी कहा कि विद्वान एकल मध्यस्थ द्वारा दिनांक 10.09.2018 को पारित पुरस्कार में उल्लेख किया गया है कि दावेदार (प्रतिवादी) का कटौती और जुर्माना लगाने का दावा, बिना किसी गलती के और प्रतिवादी को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना और सुरक्षा जमा से 33,192/- रुपये की अतिरिक्त कटौती एकतरफा और अवैध था।

4.7. विद्वान वकील ने आगे कहा कि कार्यवाही के लंबित रहने से पहले, बाद में और उसके दौरान एकमात्र मध्यस्थ के पास 1996 के अधिनियम की धारा 31(7) के अनुसार ब्याज देने का अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि 1996 के अधिनियम की धारा 34 और 37 के तहत हस्तक्षेप का दायरा बहुत सीमित है। इस तरह के तर्क के समर्थन में उन्होंने एमएमटीसी लिमिटेड बनाम वेदांता लिमिटेड (2019) 4 एससीसी 163; और हरियाणा टूरिज्म लिमिटेड बनाम कंधारी बेवरेजेज लिमिटेड (2022) 3 एससीसी 237 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा किया।

4.8. विद्वान वकील ने निम्नलिखित निर्णयों पर भी भरोसा किया:-

(ए) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट बनाम कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्शन कंपनी (2009) 4 एससीसी 546,

(बी) गोवा राज्य बनाम प्रवीण एंटरप्राइजेज (2012) 12 एससीसी 581,

(सी) बीएसएनएल बनाम नॉर्टेल नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (2021) 5 एससीसी 738,

(डी) बी एंड टी एजी बनाम रक्षा मंत्रालय, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 657,

(ई) ओएनजीसी बनाम एमसी क्लेलेैंड इंजीनियर्स एसए, (1999) 4 एससीसी 327,

(एफ) एमसीडी बनाम नटराज कंस्ट्रक्शन कंपनी (2023) एससीसी ऑनलाइन डेल. 1709.

5. पक्षों के वकील को सुना और साथ ही बार में उद्धृत निर्णयों के साथ मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

6. यह न्यायालय यह मानता है कि अपीलकर्ताओं द्वारा उपर्युक्त एनआईटी तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 14.01.2005 से 13.01.2008 के लिए जारी की गई थी, तथा इसे प्रतिवादी के पक्ष में खोला गया था, तत्पश्चात अनुबंध का निष्पादन किया गया, तत्पश्चात प्रतिवादी की अनुबंध अवधि 28.02.2008 तक बढ़ा दी गई थी; अनुबंध की शर्त के अनुसार प्रतिवादी ने उपरोक्त सुरक्षा राशि भी जमा कर दी थी; तथापि, अनुबंध की निरंतरता के दौरान अपीलकर्ताओं द्वारा प्रतिवादी पर कुछ दंड लगाए गए थे, तत्पश्चात अपीलकर्ताओं द्वारा इस संबंध में प्रतिवादी के दावे को अस्वीकार कर दिया गया था।

6.1. इसके बाद प्रतिवादी ने दिनांक 05.04.2012 को अपीलकर्ताओं के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें प्रश्नगत समझौते के खंड 37 के अनुसार एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की गई, जिसके बाद प्रतिवादी ने इस माननीय न्यायालय के समक्ष अधिनियम 1996 की धारा 11(6) के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया; इस माननीय न्यायालय ने दिनांक 05.01.2016 के आदेश के तहत उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की और उसके बाद मध्यस्थता कार्यवाही शुरू हुई।

6.2. मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान, अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी के दावे के संबंध में समय-बाधित होने के संबंध में एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई, इस प्रकार, ऐसी कार्यवाही की स्थिरता पर सवाल उठाया। उक्त प्रारंभिक आपत्तियों को विद्वान एकल मध्यस्थ द्वारा दिनांक 02.04.2017 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 10.09.2018 को अर्वाई पारित किया गया। उक्त अर्वाई को अपीलकर्ताओं द्वारा 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष विविध आवेदन दायर करके चुनौती दी गई थी, जिसे उक्त आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था।

7. इस समय, यह न्यायालय वर्तमान निर्णय के लिए घटनाओं का कालक्रम तैयार करना उचित समझता है, विशेष रूप से सीमा के मुद्दे और मामले के अन्य पहलुओं के संबंध में:-

(क) अपीलकर्ताओं और प्रतिवादी के बीच वर्ष 2005 में 3 वर्ष की अवधि के लिए समझौता किया गया था, और उसके बाद, अनुबंध को 28.02.2008 तक बढ़ा दिया गया था।

(ख) वर्ष 2007 में, प्रतिवादी ने विभिन्न राशियों के विभिन्न चालान प्रस्तुत किए, और अपीलकर्ताओं द्वारा राशि का भुगतान क्रमशः 29.03.2008 और 28.05.2008 को किया गया, प्रश्नगत कटौती के बाद।

(ग) प्रतिवादी ने कटौती की गई राशि का दावा करने के लिए दिनांक 28.07.2008 को एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके बाद अपीलकर्ताओं ने दिनांक 17.09.2008 के पत्र के माध्यम से प्रतिवादी को जुर्माना लगाने और उसी के लिए कटौती के बारे में सूचित किया।

(घ) इसके बाद, 27.04.2009 को अपीलकर्ताओं ने अंतिम बिल के लिए भुगतान किया और 15.02.2010 को अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी पर अपीलकर्ताओं द्वारा लगाए गए जुर्माने की राशि की कटौती करने के बाद सुरक्षा राशि वापस कर दी।

(ङ) 11.05.2011 को प्रतिवादी ने अपीलकर्ताओं के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें विभिन्न बिलों के साथ-साथ सुरक्षा राशि के लिए कटौती की गई राशि की वापसी की मांग की गई। इसे अपीलकर्ताओं ने 23.06.2011 को खारिज कर दिया।

(च) इसके बाद, 05.04.2012 को प्रतिवादी ने अपीलकर्ताओं के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की गई और बाद में एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए इस माननीय न्यायालय के समक्ष अधिनियम 1996 की धारा 11 (6) के तहत एक आवेदन दायर किया।

8. यह न्यायालय मेसर्स आरिफ अजीम कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स एप्टेक लिमिटेड (मध्यस्थता याचिका संख्या 29/2023, 01.03.2024 को तय) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए फैसले से अवगत है, जिसका प्रासंगिक भाग नीचे प्रस्तुत है:-

“58. सिकंदराबाद छावनी बोर्ड बनाम बी. रामचंद्रैया एंड संस जो (2021) 5 एससीसी 705 में रिपोर्ट की गई, इस न्यायालय ने अधिनियम, 1996 के तहत धारा 11(6) याचिका के संबंध में सीमा के मुद्दे का निर्धारण करते हुए इस प्रकार माना:

“19. इस मामले के तथ्यों पर उपरोक्त निर्णयों को लागू करते हुए, जहां तक मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदनों पर सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 की प्रयोज्यता का संबंध है, यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में मध्यस्थता की मांग 7-11-2006 के पत्र द्वारा की गई थी। इस मांग को 13-1-2007 के पत्र द्वारा दोहराया गया था, जिसमें अपीलकर्ता को सूचित किया गया था कि मध्यस्थ की नियुक्ति 30 दिनों के भीतर की जानी चाहिए। इसलिए, इस मामले के तथ्यों पर, समय 12-2-2007 से चलना शुरू हुआ। अपीलकर्ता का 23-1-2007 का संक्षिप्त पत्र, जिसमें कहा गया था कि मामला विचाराधीन था, 30-दिवसीय अवधि के भीतर था। 12-2-2007 को जब कोई मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया गया था, मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए कार्रवाई का कारण प्रतिवादी को प्राप्त हुआ और उस दिन से समय चलना शुरू हो गया। जाहिर है, एक बार समय चलना शुरू हो जाने के बाद, अपीलकर्ता द्वारा 10-11-2010 के पत्र द्वारा अंतिम अस्वीकृति सीमा अवधि को कोई नई शुरुआत नहीं देगी जो सीमा अधिनियम की धारा 9 के आदेश का पालन करते हुए पहले से ही चल रही है। यह मामला होने के नाते, उच्च न्यायालय यह कहने में स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण था कि चूंकि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन 6-11-2013 को दायर किए गए थे, इसलिए वे 10-11-2020 से शुरू होने वाली तीन साल की सीमा अवधि के भीतर थे। इस आधार पर, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन, स्वयं निराशाजनक रूप से समय-बाधित होने के कारण, उच्च न्यायालय द्वारा कोई मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया जा सकता था।”

(जोर दिया गया)

59. इसी प्रकार, भारत संचार निगम लिमिटेड (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने कानून की स्थापित स्थिति को लागू करने के पश्चात निम्नानुसार निर्णय दिया:

"22. वर्तमान मामले के तथ्यों पर उपरोक्त कानून को लागू करते हुए, हम पाते हैं कि धारा 11 के तहत आवेदन सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तहत निर्धारित सीमा अवधि के भीतर दायर किया गया था। नॉर्टेल ने 29-4-2020 के पत्र के माध्यम से मध्यस्थता का नोटिस जारी किया, जिसे बीएसएनएल ने 9-6-2020 के अपने उत्तर के माध्यम से खारिज कर दिया। धारा 11 के तहत आवेदन 24-7-2020 को उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था, अर्थात् मध्यस्थ की नियुक्ति के अनुरोध को खारिज करने के 3 वर्ष की अवधि के भीतर।"

(जोर दिया गया)

62. उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अनुरोध सबसे पहले याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 24.11.2022 के नोटिस के माध्यम से किया गया था और प्रतिवादी को उक्त नोटिस का अनुपालन करने के लिए नोटिस प्राप्ति की तिथि से एक महीने का समय दिया गया था। नोटिस प्रतिवादी को 29.11.2022 को दिया गया था। इसलिए, प्राप्ति की तिथि से एक महीने की उक्त अवधि 28.12.2022 को समाप्त हो गई। इस प्रकार, यह केवल इस दिन से है कि वर्तमान याचिका दायर करने की समय सीमा की घड़ी शुरू होगी। वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा 19.04.2023 को दायर की गई थी, जो कि सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 137 द्वारा प्रदान की गई 3 वर्ष की समयावधि के भीतर है। इस प्रकार, अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के तहत वर्तमान याचिका को सीमा द्वारा वर्जित नहीं कहा जा सकता है।

85. अधिनियम, 1996 की धारा 21 में प्रावधान है कि किसी विवाद के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही तब शुरू होती है जब दावेदार द्वारा दूसरे पक्ष को मध्यस्थता का आह्वान करने वाला नोटिस भेजा जाता है।

"21. मध्यस्थता कार्यवाही का प्रारंभ- जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, किसी विशेष विवाद के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही उस तिथि से प्रारंभ होती है जिस तिथि को उस विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्रतिवादी द्वारा प्राप्त होता है।"

89. इस प्रकार, मुद्दों पर कानून की स्थिति के विस्तृत विश्लेषण से, हमारा विचार है कि अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के तहत याचिका के संबंध में सीमा के मुद्दे पर विचार करते समय, न्यायालयों को दो-आयामी परीक्षण का उपयोग करके दो पहलुओं पर खुद को संतुष्ट करना चाहिए- पहला, क्या अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के तहत याचिका सीमा द्वारा वर्जित है; और दूसरा, क्या मध्यस्थता के लिए मांगे गए दावे प्रत्यक्ष रूप से मृत दावे हैं और इस प्रकार मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने की तिथि पर सीमा द्वारा वर्जित हैं। यदि इनमें से किसी भी मुद्दे का उत्तर विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजने की मांग करने वाले पक्ष के खिलाफ है, तो अदालत मध्यस्थ न्यायाधिकरण नियुक्त करने से इनकार कर सकती है।

9. यह न्यायालय इस बात से अवगत है कि मध्यस्थता कार्यवाही में सीमा अधिनियम, 1963 लागू है, और सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 137 के अनुसार, आवेदन दायर करने की सीमा अवधि 3 वर्ष है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों की श्रृंखला में तय किए गए प्रस्ताव के अनुसार भी है। त्वरित संदर्भ के लिए, उक्त अनुच्छेद 137 को नीचे दिए अनुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

भाग II-अन्य आवेदन

137	कोई अन्य आवेदन जिसके लिए इस प्रभाग में कहीं और कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है।	तीन साल	आवेदन करने का अधिकार कब प्राप्त होता है
-----	--	---------	---

10. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि उपर्युक्त विधिक प्रस्ताव वर्तमान मामले में भी लागू होता है, जिसमें प्रतिवादी द्वारा कटौती की गई राशि तथा सुरक्षा राशि की वापसी का दावा अपीलकर्ताओं द्वारा 23.06.2011 को खारिज कर दिया गया था तथा उसके बाद प्रतिवादी ने अपीलकर्ताओं के समक्ष 05.04.2012 को मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, जो दावे की अस्वीकृति की तिथि (23.06.2011) से 10 महीने से अधिक नहीं है, तथा इसलिए यह सीमा अवधि के भीतर था। यह न्यायालय यह भी मानता है कि उपर्युक्त कालक्रम के मद्देनजर, जुर्माना राशि, सुरक्षा जमा तथा उक्त जुर्माना राशि की वापसी के दावों तथा कटौती के संबंध में पक्षों के बीच पत्राचार जारी रहा, तथा इसलिए उक्त दावा अभी भी जीवित था।

10.1. इस न्यायालय ने यह भी पाया कि प्रतिवादी ने 05.04.2012 को अपीलकर्ताओं के समक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, उसके बाद 29.04.2015 को 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत आवेदन दायर किया; नोटिस की सेवा के बाद, प्रतिवादी ने 30 दिनों तक इंतजार किया, यानी 04.05.2012, और सीमा की अवधि जो 3 वर्ष है, 03.05.2015 को समाप्त हो गई, लेकिन प्रतिवादी ने 29.04.2015 को धारा 11 (6) के तहत आवेदन दायर किया; सीमा अवधि के अनुसार जो 3 वर्ष है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त निर्णय में तय कानून के अनुसार।

11. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने सही रूप से यह माना है कि प्रतिवादी के दावे पर अपीलकर्ताओं द्वारा जी.सी.सी. के अनुसार निर्णय नहीं लिया गया था, और इसलिए इसे "अपवादात्मक मामला" नहीं माना जा सकता है और धारा 64 के अनुसार, यदि वर्तमान विवाद की तरह कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसे मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए, और इसलिए, विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में किया गया निर्धारण किसी भी अस्पष्टता या किसी कानूनी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है।

12. यह न्यायालय यह भी मानता है कि प्रतिवादी का दावा समय-सीमा के अंतर्गत नहीं है और यह पूर्वोक्त चर्चा के अनुसार पूर्ववर्ती कानून में तय सीमा अवधि के अंतर्गत था और विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के साथ-साथ एकमात्र मध्यस्थता द्वारा पारित पुरस्कार कानून की दृष्टि में उचित है।

13. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि सीमा से संबंधित मुद्दे के संबंध में पक्षों द्वारा संदर्भित उपर्युक्त निर्णयों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेसर्स आरिफ अजीम कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) के हालिया मामले में पहले ही विचार किया जा चुका है।

14. इस प्रकार, उपरोक्त टिप्पणियों के प्रकाश में और वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स और उपर्युक्त मिसाल कानून को देखते हुए, यह न्यायालय वर्तमान अपील में अपीलकर्ताओं को कोई राहत देने के लिए इसे उपयुक्त मामला नहीं पाता है।

15. परिणामस्वरूप, वर्तमान अपील खारिज की जाती है। सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है।

(मुन्नुरि लक्ष्मण),जे

(डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी),जे

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।